IJNRD.ORG ISSN : 2456-4184
INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD) | IJNRD.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

"कृषि क्षेत्र में सहकारिता ऋण एवं खाद्यान्न उत्पादन के बीच सम्बन्ध"

(उत्तराखण्ड़ राज्य के विशेष सन्दर्भ में)

डा0 शनव्वर
सहायक प्राध्यापक–अर्थशास्त्र
राजकीय महाविद्यालय खाड़ी (टि0ग0) उत्तराखण्ड़
Email- shanwwar.2307@gmail.com

शोध–सार–

उत्तराखण्ड़ में सहकारिता विभाग द्वारा चलायी जा रही योजनाओ का मुख्य उद्‌देश्य न केवल कृषकों को सस्ते ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना है, बल्कि राज्य के सभी ग्रामीण तथा शहरी अंचलों को समृद्विशाली बनाते हुए विकास के स्तर को ऊंचा उठाना है। इन उद्देश्यो की पूर्ति के लिए सहकारिता विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं जैसे–सहकारी कृषि ऋण एंव अधिकोषण योजना, कृषि उत्पादन क्रय–विक्रय योजना, उपभोक्ता योजना, आदि कार्यान्वित कर सहकारी समितियों के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

मूल शब्दः सहकारिता, ऋण, पारंपरिक फसलें, उत्पादन

प्रस्तावना–

उत्तराखण्ड राज्य भौगोलिक दृष्टि से भारत का एक छोटा राज्य है परन्तु राज्य की विशेषतायें इसे भारत के अन्य राज्यों से अलग पहचान प्रदान करती है। उत्तराखण्ड राज्य में वृहत स्तर पर जैविक कृषि को प्रोत्साहित किया गया है। राज्य के पर्वतीय जनपदों में ग्रामींण आबादी की आय का प्रमुख स्रोत, कृषि एवं पशुपालन व्यवसाय है। कृषि एवं पशुपालन व्यवसाय से प्राप्त होने वाली आय जीवन स्तर तक सीमित होने से राज्य में पर्वतीय जनपदों से पलायन रोजगार के अवसरों हेतु हुआ जिससे राज्य का पर्वतीय क्षेत्र एक मनीआर्डर अर्थव्यवस्था के रूप में ही अपनी पहचान स्थापित कर सका। जनसंख्या के निरन्तर पलायन होने के फलस्वरूप पर्वतीय क्षेत्रों में महिला जनसंख्या के पक्ष में एक जनांकिकीय लाभ विकसित होता गया है परन्तु यह वर्ग कृषि कार्य हेतु पूर्णतः कुशल नहीं है। समग्र रूप से‚ राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में निम्न कृषि उत्पादकता, आगतों तथा कृषि विपणन व्यवस्था के अभाव के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं के फलस्वरूप भी राज्य की जलवायु एवं पारिस्थितिकी तंत्र इसे उच्च मूल्य कृषि उत्पादों के लिये आदर्श क्षेत्र

के रूप में स्थापित करती है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में औषधीय कृषि, जैविक कृषि के साथ—साथ पुष्प उत्पादन एवं उद्यानीकरण को प्रोत्साहित कर क्षेंत्र की आर्थिक प्रगति को तीव्रता प्रदान की जा रही है। राज्य में कृषि एवं उद्यान प्रसार कार्यक्रमों को निरन्तर विस्तार के साथ 13 जनपदों में आत्मा, परियोजना संचालित की गई। इस परियोजना के माध्यम से प्रगतिशील किसानों का चयन कर ग्राम स्तर पर कृषि कार्यक्रमों को गति प्रदान करना है।

भारत में वर्ष 1904 में सहकारिता ऋण समिति अधिनियम का गठन कर सहकारिता के माध्यम से आसान शर्तो के साथ ऋण देने की शुरूआत की गयी जो देश में सहकारिता के क्षेंत्र में पहला कदम था। इस अधिनियम के माध्यम से प्रारम्भ में केवल दो प्रकार (शहरी क्षेंत्र एंव ग्रामींण क्षेंत्रं) की समितियों का गठन किया गया। इस अधिनियम के पारित होते ही देश में सहकारिता के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यक्रम लागू किये गये जिसके कारण आगामी वर्षो में सहकारिता के क्षेंत्र में प्रगति हुई। तत्पश्चात सहकारिता के कार्यक्षेंत्र को और अधिक व्यापक एवं सुदर्ढ बनाये जाने की दृष्टि से वर्ष 1912 में नया सहकारी अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम में सहकारिता आन्दोलन के प्रसार को समुचित संरक्षण के साथ ऋण देनें के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए भी सहकारी समितियों का गठन सम्भव हो सका। सहकारी आन्दोलन में बहुमुखी प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1965 में उ0प्र0 में नये सहकारी अधिनियम का गठन किया गया। यह अधिनियम वर्ष 2003 तक उत्तराखण्ड़ राज्य में भी समान्तर रूप से लागू रहा परन्तु उत्तराखण्ड राज्य ने अपना नया सहकारी समिति अधिनियम 2003 का गठन कर, लागू किया जिसमें सहकारी समितियों को राज्य सरकार एवं निबन्धक के नियन्त्रण से पूर्ण मुक्त करते हुए समिति को पूर्ण स्वायत्ता दी गई है। इस प्रकार समितियॉ अपने कार्य क्षेंत्र एवं कार्य करने के लिये पूर्णतः स्वतन्त्र होंगी।

अध्ययन प्रविधि—

यह शोध अध्ययन द्वितीयक समंको पर आधारित है। द्वितीयक समंक के सकंलन हेतु शोध संस्थाओं व संगठनों की पुस्तकालयों, सम्बन्धित सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के कार्यालयों एवं इन्टरनेट के वैध माध्यमों का प्रयोग किया गया।

अध्ययन के उद्देश्य—

1 कृषि क्षेंत्र में सहकारिता ऋण का खाद्यान्न उत्पादन के बीच पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।

अध्ययन की समय सीमा—

शोध अध्ययन पिछले 05 वर्षों (2018—19 से 2022—23) के समंको पर आधारित है।

अध्ययन का पुर्नावालोकन–

कुमार, के0 (2022)–बोरखेड़ा की सफलता की कहानी का अध्ययन किया, जो किसी बैंक से कम नहीं है। यह सोसायटी अपने सदस्यों को विविध सेवाएँ प्रदान करती है जैसे कि अन्य बैंकों की तुलना में अधिक ब्याज दर पर सावधि जमा, किसान विकास पत्र पर ऋण सुविधा, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए ऋण, उपभोक्ता ऋण, व्यावसायिक ऋण, गृह ऋण और अन्य ऋण सुविधाएँ आदि। ताकि इस सोसायटी के कार्यक्षेत्र का सामाजिक–आर्थिक विकास हो सके।

जिदंल,मयंक ओर श्रीवास्तव, सुरभी (2021)–उत्तराखंड में सहकारी बैंकों के प्रकार, उत्तराखंड में सहकारी बैंक, उत्तराखंड में कार्यरत प्रत्येक सहकारी बैंक की शाखाओं की संख्या, उत्तराखंड में अनुसूचित और गैर–अनुसूचित सहकारी बैंक और उत्तराखंड में सहकारी बैंकों के स्वामित्व को प्रस्तुत करना है। परिणामस्वरूप, यह निष्कर्ष निकला कि उत्तराखंड में दो प्रकार के सहकारी बैंक कार्यरत हैः ग्रामीण सहकारी बैंक और शहरी सहकारी बैंक। उत्तराखंड सरकार दस जिला सहकारी बैंकों की पूँजी में योगदान करती है एक राज्य सहकारी बैंक और पाँच शहरी सहकारी बैंकों की पूँजी में योगदान करते हैं। ये पूँजी निजी हाथों में हैं।

वी0, लक्ष्मी (2018)–केरल में सहकारी बैंकों की स्थापना मुख्यतः आम लोगों के लिए हुई थी। त्रि–स्तरीय सहकारी ढाँचे में, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ आम लोगों के साथ स्वतंत्र रूप से घुलने–मिलने के लिए होती हैं। जैसा कि पहले कहा गया है, कई प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ हैं जो न केवल आम लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, बल्कि बीज, उर्वरक और कृषि उपकरण भी वितरित करती हैं। केरल राज्य सहकारी बैंक अपने जिला सहकारी बैंक के माध्यम से इन प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को हर संभव सहायता प्रदान करता है। यह केरल राज्य सहकारी बैंक की अनूठी विशेषता है।

निवेदिता (2018)– भारत में सहकारिता की शुरुआत 1904 में हुई थी। हमने भारत में अमूल जैसी कई सफल सहकारी संस्थाएँ देखी हैं। और केवल ये ही नहीं, बल्कि आजकल हम देख सकते हैं कि सहकारी संस्थाएँ बैंकिंग क्षेत्र में भी सफल हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक इसका जीवंत उदाहरण है।

अध्ययन विश्लेषण–

उत्तराखण्ड में 10 जिला सहकारी बैंक एवं उनकी 235 शाखा, 672 प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियां है जो राज्य में ऋण वितरण की सुविधा के साथ–साथ कृषकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के संग्रहण एंव विपणन में सहायता कर रही है। समितियां कृषकों को उचित दर पर कृषि कार्य हेतु रासायनिक उर्वरक एवं

उन्नतशील बीजो का वितरण एवं क्रय–विक्रय की व्यवस्था के साथ उत्पादकों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य दिलाने में सहयोग प्रदान करती है ।

तालिका–01

सहकारिता कृषि ऋण

क्र0 सं0	वित्तिय वर्ष	कृषि क्षेंत्र में वितरित धनराशि (करोड़ रू0)
01	2018-19	2253.00
02	2019-20	2009.00
03	2020-21	2231.00
04	2021-22	1622.42
05	2022-23	1709.82

स्रोत–1 स्टेट फोकस पेपर उत्तराखण्ड, नाबार्ड, 2024–25
2. स्टेट फोकस पेपर उत्तराखण्ड, नाबार्ड, 2023–24
3. स्टेट फोकस पेपर उत्तराखण्ड, नाबार्ड, 2022–23
4. स्टेट फोकस पेपर उत्तराखण्ड, नाबार्ड, 2021–22
5. स्टेट फोकस पेपर उत्तराखण्ड, नाबार्ड, 2020–21

वर्ष 2021–22 के अनुसार राज्य में कुल बोये गये क्षेंत्रफल का 29 प्रतिशत क्षेत्र गेहूँ के अन्तर्गत है आता है जिसके कारण यह प्रदेश की मुख्य फसल है। धान 24 प्रतिशत, मंडुवा 8 प्रतिशत, गन्ना 10 प्रतिशत, सांवा 4 प्रतिशत, दाल 6 प्रतिशत, तिलहन 3 प्रतिशत, मक्का 2 प्रतिशत, 2 प्रतिशत, फल एवं सब्जी 5 प्रतिशत चारा 3 प्रतिशत एवं अन्य फसलों के अन्तर्गत 4 प्रतिशत क्षेत्र आच्छादित था। शेष कृषि क्षेंत्र अन्य कृषि उत्पादों, सब्जियां, मसाले आदि के अन्तर्गत था।

तालिका –02

राज्य की विभिन्न फसलो का क्षेत्रफल

क्र0 सं0	फसल का नाम	क्षेंत्रफल (प्रतिशत में)
01	गेंहू	29
02	धान	24
03	मण्डुआ	08
04	शांवा	04
05	गन्ना	10
06	मक्का	02
07	जौ	02
08	कुल दलहन	06
09	कुल तिलहन	03
10	फल एवं शब्जी	05
11	चरा	03
12	अन्य	04

स्रोत– आर्थिक सर्वेक्षण, उत्तराखण्ड (2023–24) पेज 57

फसल क्षेंत्रफल प्रतिशत में

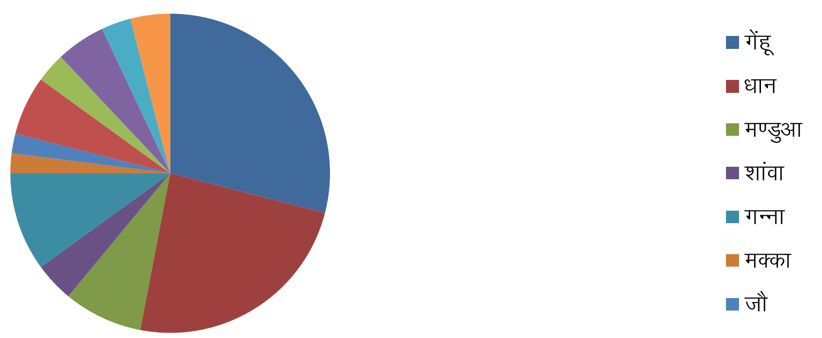

देश में खाद्यान्न सुरक्षा की मूल अवधारणा से यह सुनिश्चित करना है कि सभी नागरिकों को अपने सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए हर समय बुनियादी भोजन मिल सके। देश के अन्य राज्यों के साथ–साथ उत्तराखण्ड़ में भी बढ़ते शहरीकरण के कारण खाद्यान्न संसाधनों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। स्थिर खाद्यान्न उत्पादन तथा बढ़ती जनसंख्या को देखते हुये, भारत सरकार ने वर्ष 2007 में चावल, गेहूं एवं दाल उत्पादन को बढ़ाने के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना, 'राष्ट्रीय विकास परिषद की कृषि उप–समिति की सिफारिश के आधार पर शुरू की है। उत्तराखण्ड राज्य के चयनित जनपदों में क्षेंत्र विस्तार और सतत् रूप से कृषि उत्पादकता में वृद्धि, मृदा उर्वरता पुर्नस्थापित करने के साथ–साथ रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2012–13 से खाद्य एवं पोषण सुरक्षा तत्कालीन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन योजना की शुरूआत की गयी है। यह योजना धान, गेहूं एवं पौष्टिक अनाज हेतु उत्त्राखण्ड़ के चयनित जनपदों तथा मोटे अनाज, दलहन एवं तिलहन हेतु समस्त जनपदों में संचालित है।

तालिका –01

उत्तराखण्ड़ में खाद्यान्न उत्पादन

वर्ष	क्षेंत्रफल(000 हे0 में)	उत्पादन (000 मी0टन में)
2015-16	866.78	1756.38
2016-17	867.88	1874.50
2017-18	842.39	1920.59
2018-19	814.83	1860.21
2019-20	806.68	1892.03
2020-21	782.97	1976.63
2021-22	751.38	1886.52
2022-23	753.01	1774.73

स्रोत– आर्थिक सर्वेक्षण, उत्तराखण्ड (2023.24) पेज 57

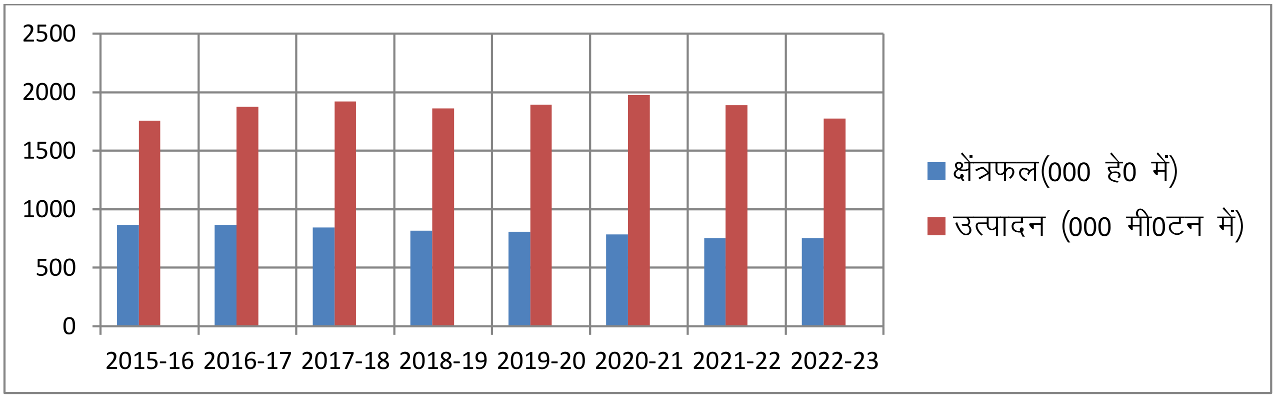

कृषि क्षेंत्र में सहकारिता ऋण एवं खाद्यान्न उत्पादन के बीच सहसम्बन्धका सूक्ष्म विश्लेषण–

x	dx (x-a)	d^2x	y	dy (y-a)	d^2y	dx dy
2253.00	630.58	397631.14	1860.21	85.48	7306.83	53901.98
2009.00	386.58	149444.10	1892.03	117.30	13759.29	45345.83
2231.00	608.58	370369.62	1976.63	201.90	40763.61	122872.30
1622.42	0	0	1886.52	111.79	12497.00	0
1709.82	87.70	7638.76	1774.73	0	0	0

x= कृषि क्षेंत्र में सहकारिता ऋण
y= खाद्यान्न उत्पादन
dx= x-1622.42
dy= y-1774.73

$\bar{x}$ = 0.204

शोध अध्ययन के विश्लेषण में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों दृष्टिकोणों का उपयोग किया गया। एकत्रित आंकड़ों का सांख्यिकीय विधियों के साथ–साथ कार्ल पियर्सन सहसम्बन्ध गुणांक विधि का उपयोग कर पिछले 05 वर्षों (2018–19 से 2022–23) के दौरान सहकारित कृषि ऋण एवं खाद्यान्न फसलों के उत्पादन का विश्लेषण किया गया और मूल्य प्राप्त किया गया तथा शोध अध्ययन में सहकारित कृषि ऋण का कृषि उत्पादन पर प्रभाव धनात्मक सहसम्बन्ध और सार्थक मूल्य देखा गया।

निष्कर्ष–

भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों की भी अपनी विशेषताएं हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि कम मात्रा में उपलब्ध होने के साथ–साथ यहां कृषि के लिए सिंचाई के संसाधनों की अत्यंत अभाव है। उत्तराखण्ड में पारंपरिक फसलें जैसे मोटे अनाज और विभिन्न स्थानीय फसल प्रजातियों का आज भी कृषि

उत्पादन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। अभी भी किसान पुरानी फसल प्रजातियों तथा परंपरागत उत्पादन तकनीक अपनाकर ही खेती कर रहे हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में अभी भी वांछित सुधार की आवश्यकता है।

सुझाव–

आज हम खाद्यान उत्पादन में आत्मनिर्भर तो बन गए परन्तु इसके उपरान्त भी आज हमें जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संशाधनों की घटती उपलब्धता के साथ–साथ आधुनिक तकनीकों के समावेंश जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए 21वी सदी में हमें कृषि उत्पादन में परम्परागत प्रणाली पर निर्भर नही रहना होगा। हमें नवाचारों के साथ–साथ तकनीकि विकास जैसे ड्रोंन तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजैंस, नैनों तकनीक एवं जैव प्रौद्योगिकी पर बल देने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में कृषकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई–कॉमर्स सें जोडनें सम्बन्धी प्रशिक्षण देना होगा जिससे वे उत्पादक एवं उपभोक्ताओं तक सीधें पहुंच सके। इसके लिए सरकार एवं वैज्ञानिक समुदायों को इस प्रकार कार्य करना होगा जिससे कि सरकारी योजनाओं, वित्तिय सहायता, उचित बाजार मूल्य, नवीनतम शोध के साथ–साथ कृषि अनुदानों की पूर्ण जानकारी कृषकों को मिलनें पर कृषि उत्पादन को बढ़ातें हुए सतत् कृषि विकास को अपना सके।

सन्दर्भ सूची–

1. उत्तराखण्ड़ में कृषि उत्पादन 2021–22, कृषि सांख्यिकी अनुभाग, कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड़
2. उत्तराखण्ड़ में कृषि उत्पादन 2019–20, कृषि सांख्यिकी अनुभाग, कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड़
3. स्टेट फोकस रिपार्ट–(2024–25) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामींण विकास बैंक, उत्तराखण्ड़ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
4. स्टेट फोकस रिपार्ट–(2023–24) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामींण विकास बैंक, उत्तराखण्ड़ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
5. स्टेट फोकस रिपार्ट–(2022–23) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामींण विकास बैंक, उत्तराखण्ड़ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
6. स्टेट फोकस रिपार्ट–(2021–22) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामींण विकास बैंक, उत्तराखण्ड़ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
7. स्टेट फोकस रिपार्ट–(2020–21) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामींण विकास बैंक, उत्तराखण्ड़ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
8. आर्थिक सर्वेक्षण–2024–25 भाग एक, अर्थ एवं संख्या निदेशालय, नियोजन विभाग विभाग, उत्तराखण्ड़
9. आर्थिक सर्वेक्षण–2023–24 भाग एक, अर्थ एवं संख्या निदेशालय, नियोजन विभाग विभाग, उत्तराखण्ड़
10. सांख्यिकीय डायरी डत्तराखण्ड़ 2023–24, अर्थ एवं संख्या निदेशालय, नियोजन विभाग विभाग, उत्तराखण्ड़
11. Performance Budget (कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका) 2024–25, सहकारिता विभाग उत्तराखण्ड़
12. http://cooperative.uk.gov.in .
13- Kumar, K. (2022). Success story of PACS Borkheda is no less than a Bank. Cooperative Perspective Journal. 57(Special Issue), pp.8-11.
14- प्रभाकर, अनुरोध (2022) www.socialsciencejournal.in Volume 5; Issue 5; September, pp-122-125
15- Jindal Mayank and Srivastava,Surabhi **(2021) International Conference on Business Research and Innovation (ICBRI 2021)) , EXCEL INDIA PUBLISHERS, pp.479-485**
16- Lekshmi. V. (2019). Kerala State Cooperative Bank as an Apex Bank – A Study. International Journal of Environment, Ecology, Family and Urban Studies, Vol. 9, Issue 2, Apr 2019, pp 91–94.
17- Nivedita. (2018). Trend Analysis of Best Performing Cooperative Bank in India: A Case Study. International Journal of Management, IT & Engineering Vol. 8 Issue 1, pp 70–75.

International Research Journal
IJNRD
Research Through Innovation